

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल

आयकर अपील सं. 26/2011

उप आयुक्त, आयकर, नैनीताल

..... अपीलकर्ता।

बनाम

मैसर्स कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल ...प्रतिवादी।

श्री अरविंद वशिष्ठ, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्री शोभित सहारिया, प्रतिवादी के वकील।

निर्णय की तिथि:23.09.2011

निर्णय

कोरम: माननीय बारीन घोष, मुख्य न्यायाधीश

माननीय यू.सी. ध्यानी, न्यायाधीश

बारीन घोष, मुख्य न्यायाधीश (ORAL)

निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए भविष्य निधि और कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने के लिए कटौती का दावा किया।

निर्धारण आदेश में, निर्धारण अधिकारी द्वारा यह दर्ज किया गया है कि ऐसे भुगतानों के संबंध में, जैसा कि उनके द्वारा अनुरोध किया गया था,

भुगतान दिखाने वाली एक तालिका प्रस्तुत की गई थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भुगतान किया गया था, लेकिन नियोक्ता के हिस्से का योगदान और कर्मचारियों के हिस्से का योगदान निर्धारित समय के भीतर नहीं किया गया था। इस आधार पर कि उक्त निधियों में योगदान, नियोक्ता के हिस्से और कर्मचारियों के हिस्से दोनों, इस तरह के भुगतान करने के लिए निर्धारित समय के भीतर नहीं किए गए थे, मूल्यांकन अधिकारी ने माना कि निर्धारिती उन योगदानों के संबंध में कटौती का हकदार नहीं था। अपील पर, सी. आई. टी. (अपील) ने अभिनिर्धारित किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी. आई. टी. बनाम एलम एक्सट्रूशंस लिमिटेड में 2009 में 319 आई. टी. आर., 306 एस. सी., उपचारात्मक प्रकृति की कार्रवाई के रूप में रिपोर्ट किया था, धारा 36 (1) (वी. ए.), के प्रावधान को हटाने के मद्देनजर योगदान की राशि का भुगतान किया गया था, हालांकि नियत तारीखों खंड पहले नहीं किया गया था, इसलिए निर्धारिती ऐसे योगदानों के लिए कटौती का हकदार था। न्यायाधिकरण द्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि की गई है, जब न्यायाधिकरण ने उक्त निर्णय के अलावा, सी. आई. टी. बनाम पी.एम. इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 2009 (313) आई. टी. आर., 0161, डी. ई. एल. में सूचित किया गया, के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के फैसले को संदर्भित किया है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्रतिपादित किया गया था, आयकर आयुक्त बनाम

विनय सीमेन्ट लिमिटेड के मामले में प्रस्तुत किया गया, 2007 (213) सी. टी. आर. (0268) एस. सी. में रिपोर्ट दी।

2. इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपील दायर की गई है, जिसमें मुख्य प्रश्न यह भी है कि क्या भविष्य निधि और कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर इस तरह के योगदान का भुगतान न करने से अनुमत कटौती अस्थिर हो जाएगी। उक्त प्रश्न ऊपर उल्लिखित निर्णयों में शामिल है।

3. इसके अलावा, अपील के समर्थन में पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नियोक्ता द्वारा कटौती की गई उक्त धनराशि में कर्मचारियों के योगदान की राशि नियत तिथि के भीतर जमा नहीं की गई थी और तदनुसार, धारा 43 बी के संदर्भ में, जो मात्र नियोक्ता के योगदान से संबंधित है, निर्धारिती कर्मचारियों के योगदान के संबंध में कटौती का हकदार नहीं था। यदि कर्मचारियों का योगदान धारा 43 बी द्वारा कवर नहीं किया जाता है, तो हालांकि, हमारे अनुसार, एक अन्य आय के रूप में माना जा सकता है, यह न्यास में नियोक्ता को ऐसी धनराशि सौंपने के समान होगा। तथ्य यह है कि, जैसा कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पाया गया है, वह संबंधित प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के दौरान निर्धारिती के हाथों में नहीं रहा, क्योंकि वास्तव में, वह धन का प्रबंधन करने वाले

प्राधिकारी के पास जमा कर किया गया था। इसलिए, निर्धारिती के हाथों में कोई अन्य आय नहीं थी।

4. उन परिस्थितियों में, कर्मचारियों के योगदान को निर्धारिती की आय के रूप में जोड़ने का प्रश्न कभी नहीं उठा। हम, तदनुसार, अपील को खारिज करते हैं।

(यू.सी. ध्यानी, न्यायाधीश)

(बारीन घोष, मुख्य न्यायाधीश)

23.09.2011

23.09.2011

अमित